MAGP
RTI Help Line
99240 85000

માહિતી અધિકાર ગુજરાત પહેલ
Mahiti Adhikar Gujarat Pahel

માહિતી અધિકાર હેલ્પ લાઈન
૯૯૨૪૦ ૮૫૦૦૦

તારીખ ૧૧-૧૦-૨૦૦૭

પ્રતિ,
તંત્રીશ્રી,

માહિતી અધિકાર કાયદો અમલમાં આવ્યે ૨ વર્ષ પૂર્ણ થયાં, **તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ના રોજ અહિંસા સપ્તાહની ઉજવણી નિમિત્તે એન.સી.પી.આર.આઈ., નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ અને નહેરુ મેમોરીયલના ઉપક્રમે આયોજિત વ્યાખ્યાન ''માહિતીનો અધિકાર - એક સત્યાગ્રહ''માં શ્રી ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધી** (રાજ્યપાલ, પશ્ચિમ બંગાળ)એ આપેલ વક્તવ્યની નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપના અખબારમાં તંત્રી પાને લેખ સ્વરૂપે સમાવવા વિનંતી.

(હરિણેશ પંડ્યા)
'માહિતી અધિકાર ગુજરાત પહેલ' વતી,

C/o, જનપથ બી-૩, સહજાનંદ ટાવર, જીવરાજપાર્ક, વેજલપુર રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૫૧
C/o, JANPATH, B-3 Sahajanand Tower, Jivrajpark, Vejalpur Road, Ahmedabad - 380 051
Phone : (079) 2682 1553, 2682 0719, Email : rtigujaratpahel@yahoo.co.in

''सूचना का अधिकार सत्याग्रह के रूप में''

आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन के उपलक्ष में २९ सप्टेम्बर २००७ को दिल्ही में
National Campaign for People's Right to Information (NCPRI),
नेशनल बूक ट्रस्ट और नहेरू मेमोरीयल द्वारा आयोजित समारोह

विषय : सूचना का अधिकार सत्याग्रह के रूप में

प्रमुख वकता : श्री गोपालकृष्ण गांधी (राज्यपाल - पश्चिम बंगाल)

: वक्तव्य :

यह आज का इंतजाम क्यों हो रहा है ?

कानून बन चुका है। बढ़िया कानून है । बहादुर कानून है । हर प्रदेश में लागू हो गया है । एक बड़े आंदोलन की इस कानून में फ़तेह हुई है ।

इस कानून ने हज़ारों के दिल उजागर किये हैं । इस कानून ने कइयों को इन्साफ दिलाया है, कई गफ़लतों, गलतियों, घूस और घोर अन्यायों का मुक़ाबला किया है ।

इस सब के बावजूद भी इस Campaign की जरूरत महसूस हुई है।

वजह?

वजह है : यह कानून जो कि भारतवासियों के कानों तक पहुंचने को था, कइयों के कानों तक पहुंचा जरूर है, पर कई औरों - करोड़ों - के कानों के ऊपर-ऊपर से सरसराता हुआ प्रवेश कर गया है दफ्तरों में।

इस बात में वैसे कोई खराबी नहीं। दफ्तरों के बिना कोई कानून नहीं चलता।

लेकिन दफ्तरों का एक अजीब तरीक़ा होता है ।

वे कानूनों को अपने कूचे में मेहमान बना देते हैं।

दफ्तरों की कोशिश होती है कि कानून को इज्ज़त मिले।

लेकिन इस इज्ज़त के बारे में ग़लत-फ़हमी रहती है।

कुछ दफ्तर समझते हैं कि कानून को इज्ज़त देने का मतलब है, कानून को कम से कम तक़लीफ हो, ज्यादा से ज्यादा आराम ।

लेकिन RTI का यह कानून आराम के लिये नहीं बना है । काम के लिये बना है । उसे मेहनत चाहिये, राहत नहीं ।

दफ्तरों को कानून में घर बनाना चाहिये, न कि कानून को दफ्तरों में ।

कानून को दफ्तरों में सिर्फ उतनी ही देर के लिये रहना पसंद है जितना कि तीर को तरकश में ।

मैं भाषण देना नहीं चाहता ।

भाषणकार दफ्तरों से भी ज्यादा कानूनों को अपने वश में कर लेते है ।

मैं तीन तपकों को संक्षेप में संबोधित करूँगा : सरकारों को, Campaign को और अन्त में उनको जिनके लिए यह Act और यह Campaign खड़ा हुआ है, यानी, आम पब्लिक को ।

पहली बात सरकारों को ।

RTI Act का एक बड़ा जिम्मा सरकारी प्रबन्धकों पर आया है । अहम ज़िम्मा है। उन को मैं कहूंगा, **RTI Act आपके हाथ का हथियार है, आपके सामने ख़तरा नहीं ।**

उसकी नोक आपके सीने पर नहीं टिकी, आप उसकी नोक पर टिके हैं । उसके साथ आगे बढ़िए, और सु-शासन को बढ़ाइए ।

उस से डरिये मत, उस से खिसकिये मत, उसे अपनाइये, उससे एक हो जाइए । उसकी मदद से हक़ीक़त को जानिए, पहचानिए, दुरुस्त कीजिए ।

सदियों से - हिन्दोस्तान में ही नहीं, सब जगह - सरकारी दफ्तर खुद को public आलोचना से अपना बचाव करने के आदी हो गये हैं। यह कुदरती बात है ।

लेकिन सरकारी दफ्तर और सरकारी कुर्सियां देश के हित के लिये बनी हैं, न कि अपने खुदके हित के लिये ।

जब भी RTI के तहत पब्लिक से कोई सवाल आता है तो सरकारी दफ्तरों को उसका स्वागत करना चाहिए और उसका पूरा, सही और सच्चा जवाब, बुलंद अल्फाज़ में, देना चाहिए ।

ऐसे अल्फ़ाज़ में, जिसमें ध्वनि हो जय दफ्तर की नहीं, 'जय तथ्य', 'जय सत्य की', और 'जय हिन्द की'।

यह हमारी खुश नसीबी है कि वजाहत हबीबुल्ला जैसे ऊँची शख्सियत वाले इन्सान आज हमारे Cheif Information Commissioner हैं । प्रदेशों में भी क़ाबिल और कर्तव्यपरायण Commissioner लोग काम में लगे हैं ।

RTI के तहत प्रदेशों में जो कमिशनर और पी.आइ.ओ. बने हैं, उनको वह सारी सुविधाएँ और सन्मान दीजिए, जो कि उन्हें मिलनी चाहिए।

RTI अधिकारियों को इस के लिए इन्तेज़ार करना पड़ें, यह सरकारों की छबि के लिए ठीक नहीं।

गोपनीयता का एक अहम सवाल है।

RTI ACT में गोपनीयता की सुरक्षा हुई है। होनी चाहिये ।

जैसे हम हैं, वैसा ही देश है ।

हमें - हम सब को - कुछ मामलों में गोपनीयता की जरूरत होती है या नहीं ? **कुछ ऐसे रिश्ते होते है, जहां गोपीनीयता जरूरी होती है। सरकार और देश के रिश्तों में भी कुछ ऐसे क्षण होते हैं, जहां गोपनीयता आवश्यक बन जाती है।**

वह कुछ नज़ाक़तों की हिफ़ाज़त के लिए होती है ।

खुलेपन का मतलब यह नहीं कि हम इन नज़ाकतों को भूल जायें।

लेकिन छिपने-छिपाने के लिए ऐसी गोपनीयता का इस्तेमाल सही नहीं । गोपनीयता का यह मतलब नहीं कि उसके तर्क में, उसकी तहों में, ऐसी बातों को, जो कि गोपनीय नहीं, गुम कर दिया जाए।

फ़ाइल नोटिंग्ज़ की बात है।

मैं सिर्फ़ इतना कह दूँ, notings करते हुए आप मुद्दे के बारे में सोचें । हक़ीकत को ध्यान में रखिए । Notes यह सोचते हुए लिखने की कोशिश न कीजिये कि 'कही आगे जाकर RTI वाली तक़लीफ़ न हो जाय।' और न ही ऐसे notes लिखने की कोशिश कीजिए जिस से RTI Act के तारामंडल में आप एक चमकता सितारा बन जाँए। The RTI Act should not make note files monosyllabic or laconic, nor should it encourage prolixity in the hope of 'RTI immortality'.

दूसरा तपका है RTI Act के निर्माताओं, समर्थकों और उसके प्रचारकों का।

आपने बहादुरी से, धीरज से, एकाग्रता से इस Act के लिए आवाज़ उठाई है। यह मेरी समझ में, हमारे संविधान की रचना के बाद, सबसे अहम रचना है। आपको आज मुबारकबाद मिला है - आगे जाकर उससे भी ज्यादह शुक्रगुज़ारी दी जाएगी। लेकिन यह काम आपने 'शुक्रिया' सुनने नहीं किया है। आपने सिद्धांत के लिए किया है। यही आपकी खासियत है।

सिद्धान्तवादी लोग, self-critical - स्वयमालोचक - होते हैं। तो उस भावना में मैं एकाध विचार रखता हूं, campaign के लिए।

आप समझिये कि bureaucracy RTI के मामले में अपने पुराने mind-set से अभी बाहर आना सीख रही है।

सदियों से, अफ्सरों ने ठकुर-सुहाती सुनी है, माई-बापी देखी है। उन्हें बताया गया है कि सवाल अफ्सर बैठे हुए करेगा, जवाब उसके सामने खड़ा हुआ इन्सान देगा ।

उन्नीस सौ निन्यान्वे की जूलई १९ को नवभारत टाइम्स में बालमुकुन्द ने लिखा था : **"हमें उस दिन का इन्तेज़ार है जब पुलिस मुख्यालय या ज़िला अधीक्षक या क्षेत्रीय प्रबन्धक के कमरे में एक आम आदमी धड़धड़ाता हुआ घुसेगा और अधिकारी उसके सम्मान में खड़ा होगा। उसके सवाल का जवाब देगा, बिना भौंहे चढ़ाए कि आखिर इस आदमी कि हिम्मत कैसे हुई यहां तक घुसने की।"**

आजादी के साठ साल बाद, अफ्सरों को सीधे सवालों को अपनाना पड़ रहा है। यह RTI Act की एक इन्किलाबी कामयाबी है।

संसदों में सवालों का सामना करने की पर्वरिश सरकारों को पहले से मिल चुकी है लेकिन यह मिली है मंत्रि मंडलों को, legislature के परिपेक्ष में। उस परिपेक्ष के बाहर, दफ्तरों के जरिए, कानूनन जवाब अब पहली बार देने पड़ रहें हैं।

RTI की ज़िम्मेदारियों में, अफ्सरों को एक नये तजुरबे का अब एहसास हो रहा है। RTI के प्रसंग में bureaucracy को आप अभी एक learner के रूप में देखिये। शिक्षक है, RTI Act । उसके निर्माता, समर्थक, campaigners - यानी आप - सह-शिक्षक हैं।

अफ्सर को धमकाइए मत, उसे समझाइये, उत्साहित कीजिए । अफसर और उत्साह? नामुमकिन! यह ख्याल मैं कइयों के दिमाग में सुन सकता हूं। यकीन कीजिए, मैंने अफसरों में बहुत उत्साह देखा है, आप चाहें तो उदाहरण भी दे सकता हूं।

जब वह कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहा है, उसको मत कहिये कि चल उठ, सर पर खड़े हो।

वह एक बड़ा पहलू सीख रहा है विश्वसनीय और transparent शासन में; शीर्षासन में नहीं।

Campaign के लिए एक और बात :

गांधीजी ने दिसम्बर ३०, १९२६ के दिन Young India में लिखा था : Those who seek Justice must come with clean hands.

'Clean hands' के कई मतलब हैं। It also means the campaign must ask the useres of the Act to use it responsibly. The campaign should make users of the Act realize the difference between stressing and straining a point, between portraying and exaggerating a situation and between emphasising and magnifying a problem. The campaign should encourage serious questions and discourage frivolous ones. अतिशयोक्ति ग़लत होती है। उससे Act को हानि पहुंच सकती है।

NGOs RTI Act के प्रचार में लगे है, उन्हे खुद को भी सवालों के लिये तैयार रहना चाहिये। उनको भी सवालों का आवागमन पसंद होना चाहिये। उन्हें खुद के हिसाब-किताब खुले रहने चाहिए - हालांकि RTI Act उन पर लागू नहीं। अरुणा ने इस के बारे में कई बार साफ़-साफ़ कहा है कि वह भी यही चाहती हैं।

Campaign का मैं यह भी कहूंगा कि आपको अपने लक्ष्य में विश्वास हो, यह जरूरी है। साथ ही आप जिस सुधार के लिए आग्रही बने हैं, उस सुधार की पूरी सफलता की संभावना में भी पूरा विश्वास रखना जरूरी है। बल्कि बहुत जरूरी है।

हो, बेशक, non-transparency का तरीका एक पत्थर। और हो बेशक यह campaign, निर्मल जल। लेकिन Lao Tzu ने ईसा से पांच सौ साल पहले लिखा है :

In all the world

is nothing more gentle

than water

yet

for wearing away

what is adamant

nothing surpasses it.

निर्मलता निर्बलता नहीं। Campaign को अपनी निर्मलता और RTI Act के users में निर्मलता के प्रचार से, बल मिलेगा। सवाल भेजने वालों के उद्देश्य और उनके आधार साफ़ हों, यह आवश्यक है। **महादेवी वर्माने अतीत के चलचित्र में लिखा है : कीचड़ से कीचड़ को धो सकना न संभव हुआ है न होगा; उसे धोने के लिए निर्मल जल चाहिए।**

सत्याग्रह शब्द को इस Campaign से जोडा गया है। इस से Campaign का काम बड़ा बनता है और मुश्किल भी। गांधी के औज़ार बल देते हैं, और दायित्व भी। Campaigners को अगर सत्याग्रह करना है तो फिर सत्याग्रह के दायित्वों को समझना होगा।

Acharya Kripalani ने १९४८ में कहा था :

'विहार में हम लोग काम करते थे तो मेरे विद्यार्थी भी मेरे साथ थे। एक दिन देखा तो कुछ विद्यार्थियों के बदन पर कुर्ता नहीं था, सिर्फ़ छोटी सी धोती और चादर थी। मैंने कारण पूछा। उन्होंने कहा ''बापू आजकल कुर्ता नहीं पहनते, इसलिये हम भी नहीं पहने।'' मैंने उनसे कहा, ''भूखे और नंगे आदमियों को देखकर कुर्ते से बापू के शरीर में जलन होती थी, आग-सी लग जाती थी, उससे बचने के लिये उन्होंने कुर्ता उतारकर फेंक दिया। तुम्हारे शरीर में वैसी जलन तो नहीं होती। तुम्हें कुर्ता फेंकने की जरूरत?''

बापू का मार्ग चलाने का मतलब यह नहीं है कि हम उनकी नक़ल उतारें। कुछ लोग तो बापू की नक़ल उतारने में अपने को बापू से भी चढ़ा-बढ़ा दिखलाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से दुनिया पर ज़ाहिर करना चाहतें हैं कि गुरु गुड़ रह गये, चेला चीनी बन गया। बापूने अपनी उम्र में इस तरह की पवित्रता का अलगपन कभी नहीं दिखाया। हम खबरदार रहें। अपने को ऊँचा और पवित्र समझनेवालों की एक जमात न बना लें। में कहना यह चाहता हूं कि हमें गांधीजी की स्पिरिट में काम करना है, किसी बाहरी चीज़ का अनुकरण नहीं करना है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले को समझ लेना चाहिये कि यह रास्ता शहीद होने का रास्ता है।'

यह थे आचार्य कृपालानी के शब्द। वे अपने में, स्वतंत्रचिन्तक के रूप में, one-man RTI Act थे। मैं जानता हूँ campaigners कभी अपने को 'चीनी' नहीं समझेंगे। लेकिन यह काफ़ी नहीं, उन्हें 'गांधी का गुड़' लेकर चलना होगा। 'गांधी का गुड़' यानी सादा सच। कड़वा या मीठा सच नहीं। सादा सच सिर्फ़ सच।

Campaigners को एक किस्म की शहादत के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और वो शहादत है indifference के तख्त पर शहादत। Cynicism के तख्त पर शहादत । सफलता हासिल करने की देर से उठती मायूसी की ढलान पर शहादत। Vilification और personal calumny की आग में शहादत । अगर campaign संगठित रहे तो ये शहादतें शह में बदल सकतीं हैं।

उन्नीस सौ बाइस में गांधीजी ने सत्याग्रह को पूरे रफ्तार के बीच रोक दिया था, जब चौरी-चौरा में २२ कन्स्तबलों का क़त्ल हुआ। 'महात्मा गांधी की जय' के नारों के बीच उनका क़त्ल हुआ था।

मंज़िल से कम नहीं, वहाँ पहुँचने के तरीक़ों की सफ़ाई।

RTI Act को सफल बनाने के लिए सत्य पर आग्रह जरूरी है। और तरीकों की सफ़ाई पर आग्रह भी।

तीसरी और आखरी बात, आम जनता से। एक नागरिक से सहनागरिकों को। **RTI Act का आप उपयोग करिये, दुरूपयोग नहीं।**

अफ्सरनुमा-इन्सान को या इन्सान-नुमा अफ़सर को तंग करने के लिये उसका इस्तेमाल क़तई मत करिए।

RTI Act अफ़सरों को सड़क की धूल से वाक़िफ़ बनाने को है। उन की नाकों को उस धूल में रगड़ने को नहीं। इस Act के जरिये ज़िम्मेवारों को ज़िम्मे के घाट पर उतारिए, किसी व्यक्ति के मान या किसी पद की गरिमा को घटाने के लिए उसका इस्तेमाल मत कीजिए।

सरकारी कर्मचारी भी जनता का हिस्सा हैं - उनको भी मैं कुछ कहना चाहूँगा : Service matters के लिए please आप RTI Act को मत उठाइए। आपके पास और रास्ते हैं - जैसे कि Tribunals.

RTI Act मूलतः उन लोगों के हित के लिए बनाया गया है जो कि साधारणतः मूक हैं, जिनकी सुनवाई नहीं, जिनके दिलों में सवाल उठ रहे हैं, उबल रहे हैं, भ्रष्टाचार के, कुशासन के। यह Act मूल में उनके लिए है। उनके लिए RTI की लाइन clear होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के निजी मामलों से RTI के phone को engaged नहीं रहना चाहिए।

RTI Act न कोई देवता है, न जिन्न। वह एक सच्चा, सुथरा और सभ्य साधन है - समाज में सच्चाई, सुथरेपन और सभ्यता को बढ़ाने का एक सही साधन।

RTI Act को पूजिए मत, न ही उससे किसी को डराइए। उससे शासन में, समाज में विश्वसनीयता बढ़ाइए।

अन्त में कुछ 'general' विचार :

RTI Act एक करार है, कड़ा करार। करारों को काग़ज़ पर छोड़ दिया जाय तो वह काग़ज़ बन कर रह जायगा। यह campaign इस RTI Act के क़रार को काग़ज़ से ऊपर हिन्दोस्तान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ने के लिए है।

मैं समझता हूं, उसकी सबसे बड़ी क़ामियाबी होगी भ्रष्टाचार से मुक़ाबिला करने की । हमारे ज़माने का dictator है रुपिया। रुपिया भी काग़ज का है। पर देखिए उसकी ताक़त! अगर रुपिया नाम का काग़ज खेल खेलता है तो यह RTI Act का काग़ज़ भी Team India बन जाय!

उन्नीस सौ इक्कीस को राजाजी को वेलूर जेल में क़ैद रखा था। स्वराज के सैनानी थे। लेकिन स्वराज के बारे में उनके ख्याल आज पढ़ने लायक हैं। स्वराज से २५-२६ साल पहले स्वराज के बारे में उन्होंने लिखा था :

We all ought to know that Swaraj will not at once or, I think, even for a long time to come, be better government or greater happiness for the people. Elections and their corruptions, injustice and the power and tyranny of wealth, and inefficiency of administration, will make a hell of life as soon as freedom is given to us.

इस सब मसलों से जूझने के लिए संस्थाएँ हैं - अदालते हैं, Election Commission हैं, Vigilance Commission हैं। RTI Act उन सब संस्थाओं के काम में सहायक बने, जन-सतर्कता के माध्यम से - यह campaign का उद्देश्य होना चाहिए।

सरकार ग़ैर-सरकारी इकाईयां और जनता, तीनों साथ-साथ सत्य की पटड़ी पर चलें, तब ही RTI Act को सफलता मिलेगी।

अरुणा, तुमको कर्तार ने एक अज़ीब-ओ-गरीब ताक़त दी है।

तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे उसूल, तुम्हारा उदाहरण हमारे लिए एक बड़ी उपाधि है।

तुम्हारे काम ने एक अध्याय खोला है, अरुणा, एक उम्मीद पैदा करी है। स्वराज में मतलब ले-आने की उम्मीद।

Old Testament में एक पंक्ति है : 'I will restore to you the years that the locust hath eaten.' (1125 Joel). RTI Act का National Campaign यह काम कर सकता है।

गांधी ने लोगों को आवाज़ दी थी । शहीद भगतसिंहने बंद कानों को खोल डाला था।

RTI Act का National Campaign यही काम करे ।

ऐसा मेरा विश्वास है ।

सूरदार के शब्दो में :
जाके कृपा पंगु गिरि लंघै,
अन्धौ को सब कछु दरिसाई,
बहिरौ सुने, गूंग पुनि बोले,
रंक चलै सिर छत्र धराई।

''માહિતીનો અધિકાર - એક સત્યાગ્રહ''

તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭ના રોજ અહિંસા સપ્તાહની ઉજવણી નિમિત્તે એન.સી.પી.આર.આઈ., નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ અને નહેરુ મેમોરીયલના ઉપક્રમે આયોજિત વ્યાખ્યાનનો સાર

વક્તા : શ્રી ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધી (રાજ્યપાલ, પશ્ચિમ બંગાળ)

માહિતી અધિકારનો કાયદો, બહાદુર છે, વજનદાર પણ છે. તેણે હજારોના દિલ ઉજાગર કર્યા છે. આ કાયદાએ કેટલાયને ન્યાય અપાવ્યો છે, ગફલતો, ભૂલો, ઘૂસ અને અન્યાયનો મુકાબલો કર્યો છે.

હવે કાયદો કચેરીમાં પહોંચ્યો છે. કાયદાના અમલ માટે કચેરી જરૂરી પણ છે. પણ કચેરીની એક અજીબ રીત હોય છે. કચેરીના એવા પ્રયત્નો હોય છે કે કાનૂનની ઈજ્જત થાય. કેટલીક કચેરી આનો ઊંધો અર્થ પણ કરે છે. કાનૂનને ઈજ્જત આપવાનો અર્થ એવો કરે છે કે કાનૂનને ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે, વધુમાં વધુ આરામ મળે. પરંતુ માહિતી અધિકારનો કાનૂન આરામ કરવા નથી બન્યો. તેને મહેનત જોઈએ છે, રાહત નહિ. કચેરીએ કાયદામાં ઘર બનાવવાનું હોય, કાયદાએ કચેરીમાં નહિ. કાયદાને કચેરીમાં માત્ર એટલો જ વખત રોકાવું પસંદ છે જેટલો વખત તીર કમાનમાં રોકાય છે.

માહિતી અધિકારના કાયદાની અગત્યની જવાબદારી સરકારી પ્રબંધકો પર આવી છે. તેમને હું કહીશ કે માહિતી અધિકાર કાયદો આપના હાથનું હથિયાર છે, તમારી સામેનો ખતરો નથી. તેની અણી તમારી છાતી પર નથી ટકી પણ તમે તેની અણી પર સવાર છો. તેની સાથે આગળ વધો, અને સુ-શાસનને હાંસીલ કરો. તેનાથી ડરશો નહિ, દુર ભાગશો નહિ, તેને અપનાવો, તેમાં એકરૂપ થઈ જાઓ, તેની મદદથી હકીકતને જાણો, ઓળખો અને દુરસ્ત કરો.

સદીઓથી માત્ર ભારતમાં જ નહિ પણ દુનિયાભરમાં સરકારી દફતર લોકોની આલોચનાથી પોતાનો બચાવ કરવા ટેવાયેલાં છે, સ્વાભાવિક છે. પરંતુ, સરકારી દફતર અને ખુરશી દેશના હિત માટે બની છે, નહિ કે પોતાના વ્યક્તિગત હિત માટે. જ્યારે પણ લોકો માહિતી અધિકાર હેઠળ સવાલ કરે ત્યારે દફતરે તેનું સ્વાગત કરવું જોઈએ અને તેનો સાચો અને પૂરો જવાબ બુલંદ શબ્દોમાં આપવો જોઈએ. એવા સ્વરે કે જેમાં ધ્વનિ 'જય દફતરની નહિ', પરંતુ 'જય તથ્ય', 'જય સત્ય' અને 'જય હિંદ'ની હોય.

માહિતી અધિકાર હેઠળ પ્રદેશમાં જે અધિકારી જાહેર માહિતી અધિકારી તરીકે નિયુક્ત થયા છે, તેમને પૂરી સુવિધા અને સન્માન અપાય, કે જે તેમને મળવું જરૂરી છે. માહિતી અધિકારના કાયદા હેઠળ નિમાયેલા અધિકારીઓને તેની પ્રતિક્ષા કરવી પડે તે સરકારની છબી માટે ઠીક નથી.

ગોપનીયતા :

માહિતી અધિકાર કાયદામાં ગોપનીયતાને રક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. મળવું પણ જોઈએ. આપણને કેટલાક સંબંધોમાં ગોપનીયતાની જરૂર જણાય છે. સરકાર અને દેશની બાબતમાં પણ કેટલીક બાબતો આવી હોય છે, જેની ગોપનીયતા જાળવવી જરૂરી બને છે. તે કેટલીક નાજુક સંબંધોની માવજત અને સુરક્ષા માટે જરૂરી હોય છે પરંતુ કશુંક છૂપાવવા આવી ગોપનીયતાની આડ લેવી તે ઠીક નથી. ગોપનીયતાનો મતલબ તેવો નથી. તેના મૂળમાં, તર્કમાં જે વાતો ગોપનીય નથી તેને ગુમ કરી દેવામાં આવે.

ફાઈલ નોટીંગ્સ :

હું એટલું જ કહીશ કે નોંધ લખતી વખતે માત્ર મુદ્દા અંગે વિચાર કરજો. હકીકતને નજર સમક્ષ રાખજો. નોંધ લખતી વખતે આગળ જતાં કોઈ માહિતી અધિકારમાં માંગશેની બીક રાખશો નહિ.

માહિતી અધિકાર સમર્થકો - પ્રચારકો :

આપે બહાદુરી, ધીરજ અને એકાગ્રતા પૂર્વક આ કાયદા માટે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. મારા માનવા પ્રમાણે ભારતના બંધારણની રચના પછીની આ સૌથી મહત્ત્વની રચના છે. ધન્યવાદ, પણ આ કામ તમે ધન્યવાદ મેળવવા નથી કર્યું. સિદ્ધાંત માટે કર્યું છે અને તે તમારી ખાસીયત છે. સિદ્ધાંતવાદી લોકો સ્વયમાલોચક (Self Critical) હોય છે.

અમલદારો પોતાની જુની મનોદશામાંથી બહાર આવી રહ્યા છે. તેમને શીખવવામાં આવ્યું છે કે સવાલ ખૂરશીમાં બેઠેલો કરે, અને સામે ઉભેલો તેનો જવાબ આપે. આઝાદીના ૬૦ વર્ષ પછી અફસરોને સીધા સવાલોનો સામનો કરવાનો આવ્યો છે. આ માહિતી અધિકાર કાયદાની ઈન્કલાબી કામયાબી છે. સંસદમાં સવાલોનો સામનો કરવાની તાલીમ સરકારને પહેલાંથી મળી ચૂકી છે. તેનાથી તે ટેવાયેલા છે પણ તે સિવાય દફતરો મારફતે તેમણે પહેલીવાર જવાબો આપવા પડી રહ્યા છે. અમલદારો શીખી રહ્યા છે. માહિતી અધિકારનો કાયદો શિક્ષક છે અને તમે સહ-શિક્ષક.

માહિતી અધિકાર ઝૂંબેશ માટે :

સંગઠનો માહિતી અધિકારના પ્રચારમાં લાગ્યાં છે. તેમણે પોતે પણ સવાલોનો સામનો કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. તેમને પણ સવાલોનું આવા-ગમન પસંદ પડવું જોઈએ. તેમણે પોતાના હિસાબ-કિતાબ ખૂલ્લા મૂકવા જોઈએ. અરૂણા રોયે આ અંગે ઘણી વખત સાફ-સાફ કહ્યું છે. મહાદેવી વર્માએ ''અતીત કે ચલચિત્ર''માં કહ્યું છે કે કીચડથી કીચડને ધોવાનું ન કદી બન્યું છે ન બનશે. તેને ધોવા માટે નિર્મળ જળ જોઈએ.

માહિતી અધિકાર - સત્યાગ્રહ

સત્યાગ્રહ શબ્દને આ ઝૂંબેશ સાથે જોડવામાં આવ્યો છે. તેનાથી ઝૂંબેશનું કામ પણ મોટું થાય છે અને મુશ્કેલી પણ. ગાંધીનો ઓજાર બળ આપે છે, અને જવાબદારી પણ. ઝૂંબેશકારોને જો સત્યાગ્રહ કરવો છે તો સત્યાગ્રહની જવાબદારીને પણ સમજવી પડશે.

ઝૂંબેશકારોએ એક પ્રકારેની બલિદાન આપવા તત્પર રહેવું પડશે. અને તે બલિદાન છે indifference ના તખ્ત પર, cynicismના તખ્ત પર શહાદત, સફળતા વિલંબમાં પડતી જોઈને ઉઠતી નીરાશાના ઢોળાવ પર શહાદત, Vilification અને Personal Calumny ની આગમાં શહાદત. જો ઝૂંબેશ સંગઠીત રહે તો આ શહાદતો 'શહ'માં બદલાઈ શકે છે.

૧૯૨૨ માં ગાંધીજીએ પૂર્ણગતિથી ચાલતા સત્યાગ્રહને રોકી દીધો હતો, જ્યારે ચૌરી-ચૌરામાં બાવીસ હત્યા થઈ. ''મહાત્મા ગાંધીની જય''ના નારા વચ્ચે તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી. મંજીલ જેટલું જ મહત્ત્વ ત્યાં પહોંચવાની રીતની શુધ્ધતાનું છે. RTI Act ને સફળ બનાવવા માટે સત્ય પરનો આગ્રહ જરૂરી છે, અને રીત-રસમોની સફાઈ માટેનો આગ્રહ પણ તેટલોજ જરૂરી છે.

નાગરિકો માટે :

RTI Act નો તમે ઉપયોગ કરો દુરુપયોગ નહિ. અફસરનુમા-ઈન્સાન ને કે ઈન્સાન-નુમા અફસરને તંગ કરવા તેનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

RTI Act સરકારી અફસરોને રસ્તાની ધૂળથી વાકેફ કરવા માટે છે, તે ધૂળમાં તેમનું નાક રગડવા નહિ. આ કાયદાથી જવાબદારોને જવાબદેહિતાના ઘાટ પર લાવો. કોઈ વ્યક્તિના માન કે પદની ગરિમાને હાની પહોંચાડવા તેનો ઉપયોગ કરશો નહિ.

સરકારી કર્મચારી :

સરકારી કર્મચારી પણ જનતાનો હિસ્સો છે, તેમને મારે ખાસ કહેવું છે કે, Service Matters માટે મહેરબાની કરીને RTI Act નો ઉપયોગ કરશો નહિ. આપની પાસે બીજા રસ્તા પણ છે.

RTI Act મૂળભૂત રીતે તે લોકોના હિતમાં બનાવવામાં આવ્યો છે કે, જે સાધારણ રીતે મૂક છે, જેમને કોઈ સાંભળતું નથી, જેમના મનમાં સવાલો ઉદ્‌ભવી રહ્યા છે, ઉકળી રહ્યા છે, ભ્રષ્ટાચારના, કુશાસનના. આ કાયદો તેમના માટે છે. આવા લોકો માટે RTI ની લાઈન clear હોવી જોઈએ. સરકારી કર્મચારીઓએ અંગત મામલા માટે આ લાઈન engaged રાખવી જોઈએ નહીં.

RTI Act ની પૂજા કરશો નહિ, કે ના કોઈને તેનાથી ડરાવશો. તેનાથી સમાજની શાસનમાં વિશ્વસનીયતા વધારો.

અંતમાં એક વિચાર...

RTI Act એક કરાર છે, કરારને કાગળ પર છોડી દેવામાં આવે તો તે માત્ર કાગળ બનીને રહી જશે. આ RTI ઝૂંબેશ RTI Act ના કરારને કાગળ પરથી ઉપર ઉઠાવી હિન્દુસ્તાનની રોજબરોજની જીંદગી સાથે જોડવા માટે છે.

હું માનું છું કે, તેની સૌથી મોટી સફળતા હશે ભ્રષ્ટાચારનો સામનો કરવાની. આપણા જમાનાના dictator છે રૂપિયા. તે પણ કાગળના છે, પણ જુઓ તેની તાકાત, જો રૂપિયા નામનો કાગળ ખેલ ખેલી શક્તો હોય તો આ RTI Act નો કાગળ પણ 'ટીમ ઈન્ડીયા' બની જાય.

અરૂણા રૉય તમને કર્તારે એક અજીબો-ગરીબ તાકાત આપી છે. તમારી હિંમત, મૂલ્યો, તમારું ઉદાહરણ માત્ર અમારા માટે પદવી સમાન છે. તમારા કામે એક નવો અધ્યાય ખોલ્યો છે. એક નવી આશા જન્માવી છે. ''સ્વરાજને અર્થપૂર્ણ બનાવવાની આશા. ગાંધીએ લોકોને અવાજ આપ્યો, ભગતસિંહે બંધ કાન ખોલી નાખ્યા હતા. RTI Act ની રાષ્ટ્રીય ઝૂંબેશ પણ તે જ કામ કરશે એવો મારો વિશ્વાસ છે.''

સુરદાસના શબ્દોમાં :

જા કે કૃપા પંગુ ગિરિ લંઘૈ,
અન્ધોં કો સબ કુછ દરિસાઈ
બહિરૌં સુને, ગૂંગ પુનિ બોલે,
રંક ચલે સિર છત્ર ધરાઈ.